passengers. We have so many rivers. Why is there on such policy to revive it? Why is it running in losses?

SHRI T. R. BAALU: Mr. Chairman, Sir, I can pass on the answer to the hon. Member detailing whatever I have said previously, I do not want to repeat a lengthy reply.

DR. (SHRIMATI) NAJMA A. HEPTULLA: Why is it not running in profit? ...(*Interruption*)...

SHRI T. R. BAALU: Sir, I can pass it on to the Hon'ble Member. A lot of things are to be discussed on this. A detailed letter will be sent to her.

Subsidence in Eastern Coal Fields Limited

*224. SHRI CHITTABRATA MAJUMADAR:†
SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:

Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether there has been serious subsidence in Sanctoria area of Eastern Coal Fields Ltd.;

(b) if so, the details thereof;

(c) the immediate measures taken, so far to rehabilitate and compensate the affected people; and

(d) the short term/long term measures taken to prevent such subsidence?

THE MINISTER OF COAL (SHRI SHIBU SOREN): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) A subsidence occured in Sanctoria village on 27.11.2004 at about 2.20 P.M. above the old workings of Sanctoria colliery. Cracks have been noticed in 56 houses. These workings were made during the period 1912 to 1923. No mining activites have been undertaken at this place since the formation of Eastern Coalfields Limited.

---

†The question was actually asked on the floor of the house by Shri Chittabrata Majumdar.

(c) 24 houses were considered for immediate vacation and the residents were allotted temporary accommodation nearby. Rest of the houses are under observation. Central Mining Research Institute (CMRI), a scientific Institution has been entrusted the job to study and suggest further measures. Stabilisation work with sand the filling through borecholes is already under progress as per approved scheme of Sanctoria village and till November 2004, 21,000 cum. of sand has been filled up in last three years. The Sanctoria village is also earmarked for rehabilitation as per action plan to control fire and subsidence in Raniganj coalfield. The work of rehabilitation is to be taken up by the State Government. West Bengal State Government has entrusted the job to Asansol-Durgapur Development Authority (ADDA). ADDA has been requested to take up the job of rehabilitation on priority for Sanctoria village.

(d) Stabilisation with sand stowing will continue at Sanctoria village to control further subsidence wherever feasible.

SHRI CHITTABRATA MAJUMDAR: Sir, the reply of the Minister is very unsatisfactory. Keeping in view the repeated cases of subsidence in the same area in 1969, 1991, 1999 and now in 2004, (a) what action have been taken to ensure that stabilisation work with sand is done technically to avoid such subsidence?

(b) Why no action was taken before hand for rehabilitation when the area was found unsafe because of repeated cases of subsidence?

श्री शिबू सोरेन: महोदय, जहां-जहां कोयला खनन होता है, निश्चित रूप से वहां पर गड्ढे होते हैं और जगह खाली होती है। जगह खाली होने पर यह नियम है कि उसमें बालू भरा जाता है ताकि वह जगह ठीक हो सके। ये घटनाएं जहां पर हुई हैं, वहां की खदान अंग्रेजों के जमाने में चलती थी। जब से राष्ट्रीयकरण हुआ है तब से वहां पर कोयला खनन का काम नहीं हुआ है, बाकी और जगह पर हुआ है। इसके लिए हमेशा सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास किया है। चूंकि मैं कोयला इलाके का ही आदमी हूं, वहां पर गड्ढा होना ही है और उसके बाद बरसात आनी है, उसी प्रकार से उसमें बालू भी घुसाने का, उसका उपाय है।

श्री सभापति: आप क्वेश्चन का जवाब दे दें।

श्री शिबू सोरेन: कम्पनी की तरफ से पैसा खर्च करने में कहीं कोई कमी नहीं है। सन् 2003 में एक सचिव समिति बनी थी और इसको पूरी तरह से रोकने के लिए एक योजना बनी है। यह योजना बीस वर्ष तक के लिए है। बीस वर्ष तक यह गारंटी होगी कि कोयला निकालने के समय कोई

एक्सिडेंट न हो। जिस तरह पंचवर्षीय योजना होती है यह उसी तरह से है और इसका रिहेबिलिटेशन कराना जरूरी हैं। इसलिए इसमें राज्य सरकार की मदद जरूरी है। वहां पर जो गरीब बैठे हैं, वे वहां से बहुत मुश्किल से उठते हैं। नियम के तहत, उनको बहुत पहले से ही जगह खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन वे वहां से नहीं हटे। वे अक्सर वहां से हटते नहीं हैं, इसलिए उनको वहां से हटाना चाहिए। इन घटनाओं को बंद करने के लिए उनको वहां से हटाना जरूरी है।

SHRI CHITTABRATA MAJUMDAR: Sir, I put my second question though the answer to the first one is not satisfactory, When 176 families are affected and another 700 families are also facing danger of subsidence, the reply doesn't say anything about the compensation to the affected people. Will the Government ensure suitable compensation to the subsidence-affected people.?

श्री शिबू सोरेन: महोदय, निश्चित रूप से हम लोग इसे करेंगे। अभी जैसे यहां क्रैक हुआ था, वहां जाकर शिनाख्त किया गया तो जो लोग तत्काल प्रभावित हो रहे थे, उनको तुरंत जगह दी गई और पूरी तरह से उसकी छान-बीन हो रही है, उनको उठाने की और इसकी गारन्टी के साथ। इसका प्रोजेक्ट बना हुआ है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, this problem is not only limited.

खाली रानीगंज की बात नहीं हैं और मंत्री जी को भी मालूम है कि रानीगंज या झरिया कोल फील्ड्स में सबसिडेंस, बहुत सालों से यह प्राब्लेम चली आ रही है और उसके लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम भी थी। रीहैबिलिटेशन कंट्रोल ऑफ फायर इन झरिया एंड रानीगंज फील्ड्स। जहां तक मेरी जानकारी है इसके लिए जो फंड्स प्लान, नाइन्थ प्लान में जो एलोकेशन था, उस प्लान के फंड से इसमें एक्सपेंडीचर भी नहीं हुआ, पैसा खर्च भी नहीं हुआ। उस एरिया में एक ऐसी बीमारी है, उस एरिया के लोग इतने त्रस्त हैं कि जब एक्सीडेंट हो तब उसके ऊपर एक्शन लें, यह जरूरी नहीं है। मेरा प्रश्न यही है कि इसको देखते हुए क्या कोई स्पेशल टास्क फोर्स यह सरकार अभी गठित करेगी? एक स्पैशल टॉस्क फोर्स के बारे में, स्कीम जो ऑलरेडी है, उसके बारे में तथा सबसिडेंस और फायर बोथ, इन रानीगंज एंड झरिया कोल फील्ड्स के बारे में एक विदिन द टाइम बाउन्ड प्रोग्राम देगी, पैसा जितना है वह खर्च करेगी और रेगुलर वहां से मॉनिटर होगा? और जो रिपोर्ट मिनिस्ट्री से.., रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए।

श्री सभापति: बोलिए।

श्री दीपांकर मुखर्जी: यह एश्योरेंस दे दीजिए।

श्री सभापति: सोच समझ कर देना एश्योरेंस।

श्री शिबू सोरेन: महोदय, यह जरूरी है कि जब तक राज्य सरकार और कोयला पदाधिकारियों की बैठक नहीं होगी, उसके रीहैबिलिटेशन करने की व्यवस्था नहीं होगी। लोगों को हटाने के लिए एक टास्क फोर्स बना हुआ है पहले से ही यह सीमित बनी हुई है और काम भी चल रहा है। यदि जरूरत पड़ेगी तो हम लोग और उपाय करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Q No. 225

[The questioner (Shri Mangni Lal Mandal) was absent. For answer vide page 32.]

Over bridge on NH-5

*226. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Road Safety Forum had demanded a pedestrian overbridge at Gundugolamu village on National Highways No. 5;

(b) whether it is a fact that NHAI is reluctant to receive and entertain suggestions from road safety experts and activists; and

(c) the steps proposed to correct this situation immediately?

THE MINISTER OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SHRI T. R. BAALU): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir. The demand for a pedestrian overbridge at Gundugolanu village on National Highway No. 5 was received from the Road Safety Forum of Polavaram, West Godavari District of Andhra Pradesh and was examined in detail. The provision of Pedestrian overbridges is considered at locations near built up areas consisting of schools, markets, shops, temples, hotels, cinema halls etc. on both sides of carriageway, where volume of pedestrian traffic crossing a wide carriageway is large. Such conditions, however, do not exist at the Gundugolanu junction to justify a pedestrian overbridge. The same has been communicated to the President, Road Safety Forum.